

बेटी, बगिया और पंचायत: पिपलांत्री की अनूठी पहल

डॉ. सोनल मोबार रॉय

DOI: <https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.194--205>

ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

राजस्थान का पिपलांत्री गाँव इस बात का सशक्त उदाहरण है कि स्थानीय परंपराएँ और सरकारी योजनाएँ जब एक-दूसरे से जुड़ती हैं, तो ग्राम विकास केवल नीतिगत दस्तावेज़ नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत सामाजिक परिवर्तन का रूप ले लेता है। बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा ने यहाँ न केवल लैंगिक समानता की चेतना को प्रबल किया, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरणीय पुनर्जीवन को भी सामुदायिक उत्सव में बदल दिया। इस सांस्कृतिक पहल को ग्राम पंचायत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसे कार्यक्रमों से जोड़ा, जिससे यह केवल प्रतीकात्मक न रहकर आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थायी बनी। अध्याय में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिलाओं की हिस्सेदारी 59% तक पहुँचना यह दर्शाता है कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिला श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण का प्रमुख साधन बन चुकी है। विशेषकर राजस्थान में यह आँकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक (66-68%) है, जिसने पिपलांत्री जैसे गाँवों में महिलाओं की भूमिका को श्रमिक से आगे बढ़ाकर सामाजिक नेतृत्व तक पहुँचाया है। यह अध्याय तर्क प्रस्तुत करता है कि पिपलांत्री मॉडल केवल पर्यावरणीय पहल या सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि सतत् विकास लक्ष्यों की स्थानीय व्याख्या भी है। इसमें गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और पारिस्थिति की संरक्षण जैसे आयाम एक साथ जुड़े हैं। पिपलांत्री यह सिखाता है कि जब पंचायत और समुदाय मिलकर कार्य करते हैं, तो अनुभव नीति में बदलते हैं और संवाद से विकास की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है।

मुख्य शब्द: महिला भागीदारी, ग्राम पंचायत, सतत् विकास, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय संरक्षण

प्रस्तावना

भारत के गाँव केवल भौगोलिक इकाइयाँ नहीं हैं; वे सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपरा और जीवन-निर्वाह की धुरी हैं। आज भी ग्रामीण भारत लगभग 65% आबादी का घर है, और वहीं से देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोकतांत्रिक सहभागिता की जड़ें पोषित होती हैं। इस संदर्भ में *ग्राम पंचायतें* केवल प्रशासनिक संस्थाएँ नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक ऊर्जा की वाहक हैं।

राजस्थान के राजसमंद ज़िले का एक छोटा-सा गाँव पिपलांत्री आज ग्राम विकास की प्रयोगशाला माना जाता है। पिपलांत्री गाँव उदयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर, राजसमंद ज़िले की *रेलमगरा तहसील* में स्थित है। यह गाँव अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है और ऐतिहासिक रूप से *खनन गतिविधियों* के लिए जाना जाता रहा है। पास के क्षेत्रों में संगमरमर और अन्य खनिजों की खदानें हैं, जिसने लंबे समय तक गाँव के पर्यावरण और जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिपलांत्री की कुल जनसंख्या लगभग 5, 000–6, 000 के बीच है (2011 की जनगणना और स्थानीय स्रोतों के अनुसार)। गाँव का सामाजिक ढांचा विशिष्ट रूप से राजस्थानी ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ कृषि और पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन खनन उद्योग के कारण यहाँ के पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडराने लगा था (येल रिब्यू ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, 2016; आईजेएसआरएसटी, 2017)। खनन की वजह से:

- जलस्तर लगातार नीचे जा रहा था, कई क्षेत्रों में पानी 800–900 फीट की गहराई से ही मिल पाता था (मिशन सस्टेनेबिलिटी, 2024)।
- मिट्टी का कटाव और हरित आवरण में भारी कमी आई थी (ग्लोबल बिज़नेस सर्टिफिकेशन इंक., 2019)।
- खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट ने भूमि की उर्वरता और आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषित किया (आईजेएसआरएसटी, 2017)।
- गाँव गर्म और शुष्क जलवायु में और भी जलविहीन तथा असुरक्षित होता चला गया (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2021)।

इस संदर्भ में पिपलांत्री ने अपने लिए एक *वैकल्पिक रास्ता* चुना। जब स्थानीय नेतृत्व और ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि बेटी के जन्म को पौधारोपण से जोड़ा जाएगा, तब यह केवल एक सामाजिक संदेश नहीं था, बल्कि *पर्यावरणीय पुनर्जीवन* और *जल संकट से निपटने की रणनीति* भी थी (द ट्रिब्यून इंडिया, 2024)। आज पिपलांत्री को “मॉडल विलेज” कहा जाता है।

जिस गाँव को कभी *खनन और जल संकट* ने असुरक्षित बना दिया था, वही गाँव आज *सतत विकास, लैंगिक न्याय और पंचायत आधारित नवाचार* का आदर्श बन गया है (आइडियाज़ फ़ॉर

इंडिया, 2025; संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2021)। यहाँ विकास का अर्थ केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह *लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता* का सम्मिलित दर्शन है। यह गाँव इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब पंचायत, समाज और परंपरा एक साथ खड़े होते हैं, तो विकास न केवल योजनाओं से, बल्कि *सांस्कृतिक मूल्यों* से भी आकार लेता है। राजस्थान के राजसमंद ज़िले का पिपलांत्री गाँव विकास का एक प्रेरणादायी मॉडल बन चुका है। ग्राम पंचायतें अक्सर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के औजार के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद ज़िले का पिपलांत्री गाँव बताता है कि जब स्थानीय संस्कृति, पर्यावरणीय चेतना और सामुदायिक भागीदारी एक साथ आती हैं, तो गाँव *नीति का निष्क्रिय केंद्र* नहीं, बल्कि *परिवर्तन का सक्रिय स्रोत* बन जाता है। इस गाँव ने एक अद्भुत पहल की—हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाना। यह प्रतीकात्मक कदम धीरे-धीरे एक *सामुदायिक नवाचार* बन गया, जिसने न केवल पर्यावरण को संवारा बल्कि बेटियों के प्रति सोच और पंचायत के विकास मॉडल को भी बदल डाला (इंडियन एक्सप्रेस, 2023; द प्रिंट, 2024; प्रेस सूचना ब्यूरो, 2023)।

राजस्थान के राजसमंद ज़िले का एक छोटा-सा गाँव—पिपलांत्री—इसी सामाजिक ऊर्जा का जीवंत उदाहरण है। यह गाँव एक अनूठे मॉडल के रूप में जाना जाता है जहाँ *बेटी, बगिया और पंचायत* एक साथ मिलकर विकास की नई परिभाषा गढ़ते हैं। बेटी का जन्म अब केवल परिवार की निजी घटना नहीं बल्कि पूरे गाँव का सामूहिक उत्सव है। इस उत्सव को पौधारोपण और पर्यावरणीय संरक्षण से जोड़ा गया है। यह न केवल *लैंगिक समानता* को बढ़ावा देता है बल्कि सतत विकास और ग्राम पंचायत के नेतृत्व की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है।

पहल की शुरुआत

पिपलांत्री की अनूठी पहल की नींव 2000 के दशक में उस समय रखी गई जब गाँव की बच्चियों और पर्यावरण को लेकर एक सामाजिक संकल्प लिया गया। गाँव में यह परंपरा शुरू हुई कि हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाएंगे। यह प्रतीकात्मक कदम समय के साथ सामूहिक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। इसकी अगुवाई पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने की, जिनकी बेटी की असामयिक मृत्यु ने इस अभियान को व्यक्तिगत दर्द से सामुदायिक संकल्प में रूपांतरित कर दिया। इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में पूरी पंचायत ने भाग लिया।

इस अवसर पर बेटी के माता-पिता और समुदाय की ओर से ₹21, 000 तथा पंचायत की ओर से ₹10, 000 बेटी के नाम पर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट जमा किए जाते हैं। इस प्रकार यह पहल सर्वव्यापी हो गई और समस्त ग्रामवासी इसका हिस्सा बने। माता-पिता एक अफ़िडेविट पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे बेटी की शिक्षा जारी रखेंगे, उसका समय से पूर्व विवाह नहीं करेंगे और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करेंगे। इसके अतिरिक्त,

ग्राम पंचायत इस पूरी प्रक्रिया को मनरेगा से जोड़कर सामूहिक श्रम और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराती है। पिपलांत्री अब न केवल *पर्यावरणीय पुनरुद्धार बल्कि लैंगिक न्याय और पंचायती नवाचार* का प्रतीक माना जाने लगा है (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2021)।

बेटी और बगिया का संगम

बेटी और बगिया का संगम केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक रूपांतरण का आधार है। पहले जहाँ बेटी के जन्म को बोझ समझा जाता था, वहीं अब पौधारोपण की परंपरा ने उसे पूरे गाँव की धरोहर और सामूहिक गर्व का विषय बना दिया है। प्रत्येक पौधा किसी बेटी के नाम से जुड़ा होता है, जिससे गाँववाले न केवल उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, बल्कि उसकी देखभाल को सामाजिक कर्तव्य समझते हैं। इस प्रक्रिया ने सामुदायिक चेतना को गहरा किया है, क्योंकि बेटियों और पौधों दोनों की सुरक्षा अब ग्राम सभा और पंचायत की साझा जिम्मेदारी बन चुकी है (ग्लोबल बिज़नेस सर्विफिकेशन इंक., 2019; आईजेएसआरएसटी, 2017)। यह मॉडल केवल परंपरा और आधुनिकता का सम्मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या का समाधान सांस्कृतिक नवाचार से खोजने का उदाहरण है। इसने ग्रामीण समाज में एक नई सामूहिक पहचान गढ़ी है, जहाँ बेटी का भविष्य और गाँव का पर्यावरण एक-दूसरे से अविभाज्य हो गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस पहल ने ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। पौधों की देखभाल में महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने सामाजिक पूँजी को सुदृढ़ किया है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया है। बेटियों के नाम से जुड़ी बगिया अब केवल हरियाली नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक सहभागिता का भी प्रतीक बन चुकी है। इसने ग्रामीण समाज को यह संदेश दिया कि बेटी और बगिया, दोनों मिलकर ही जीवन की स्थिरता और विकास का आधार हैं।

केस-वृत्तांत: सोनी की बगिया

उदाहरण के तौर पर, जब गाँव की एक किसान परिवार की बेटी सोनी का जन्म हुआ, तो पंचायत की परंपरा के अनुसार 111 पौधे लगाए गए। सुनीता की माँ कहती हैं कि *“पहले बेटी होने पर लोग सहानुभूति जताते थे, पर अब लोग बधाई देते हैं और पेड़ लगाने में साथ आते हैं। हमें लगता है कि बेटी अकेली नहीं है, पूरा गाँव उसके साथ है।”* सोनी के नाम पर लगाए गए नीम और आम के पौधे अब बड़े पेड़ बन चुके हैं। वे न केवल छाया और हरियाली दे रहे हैं, बल्कि गाँव के बच्चों के खेलने और पढ़ने की जगह भी बन गए हैं।

यह छोटी-सी कहानी दिखाती है कि कैसे एक बच्ची और उससे जुड़े पौधे दोनों गाँव की सामूहिक पहचान का हिस्सा बन गए हैं। यह पहल केवल पर्यावरण सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गाँववालों की मानसिकता और भावनाओं में गहराई तक उतर चुकी है।

पंचायत की भूमिका और सामुदायिक सहभागिता

पिपलांत्री की विशेषता यह रही कि यहाँ ग्राम पंचायत ने इस पहल को केवल सांस्कृतिक अनुष्ठान के स्तर पर सीमित नहीं रहने दिया। अक्सर गाँवों में कोई सामाजिक परंपरा उत्साह से शुरू होती है, लेकिन समय बीतने के साथ वह केवल प्रतीकात्मक रह जाती है। पिपलांत्री की पंचायत ने इसके विपरीत कार्य किया उसने इस पहल को सरकारी योजनाओं और संस्थागत प्रक्रियाओं से जोड़कर स्थायी रूप दिया। यही कारण है कि यह आंदोलन केवल व्यक्तिगत प्रेरणा तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे गाँव की सामूहिक जीवन-शैली में गहराई से उतर गया।

ग्राम पंचायत ने *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)* का उपयोग इस दिशा में विशेष रूप से किया। वृक्षारोपण, तालाब खुदाई, नालों और चेक डैम का निर्माण, जल संरक्षण के प्रयास, इन सबको मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई। इसका लाभ यह हुआ कि एक ओर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पुनर्जीवन हुआ, दूसरी ओर गाँव के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो गया। इस तरह पर्यावरण और आजीविका, दोनों लक्ष्यों को साथ-साथ पूरा किया गया। साथ ही, पंचायत ने *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन* और महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस आंदोलन से जोड़ा। एलोवेरा और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया, ताकि महिलाएँ केवल पौधारोपण तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी देखभाल और उनसे आय अर्जित करने में भी सक्रिय भागीदारी निभाएँ। इससे महिला आय में वृद्धि हुई और उनके भीतर आत्मनिर्भरता की भावना भी सुदृढ़ हुई। यह पहल दिखाती है कि पंचायत ने केवल प्रतीकात्मक अनुष्ठान नहीं किया, बल्कि इसे आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की योजना भी बनाई।

इसके अतिरिक्त, सामुदायिक बंधन को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा को भी सक्रिय किया गया। ग्राम सभा की बैठकों में यह समीक्षा की जाने लगी कि पौधों की देखभाल किस स्तर पर हो रही है और परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार यह पहल केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रही बल्कि एक सामाजिक अनुबंध (social contract) का रूप ले चुकी है। बेटियों की शिक्षा और पौधों की सुरक्षा अब केवल व्यक्तिगत दायित्व नहीं रहे, बल्कि पूरे समुदाय की साझा जिम्मेदारी बन गए (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2021; आइंडियाज़ फ़ॉर इंडिया, 2025)।

इस प्रकार पिपलांत्री की पंचायत ने सांस्कृतिक पहल को संस्थागत रूप प्रदान किया। उसने परंपरा को आधुनिक नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ा और सामुदायिक सहभागिता के जरिए इसे टिकाऊ बनाया। यही कारण है कि पिपलांत्री का उदाहरण अन्य गाँवों और नीतिनिर्माताओं के लिए प्रेरणा बन सका।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

पिपलांत्री की पहल ने केवल एक सांस्कृतिक अनुष्ठान को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने गाँव की सामाजिक संरचना, पर्यावरणीय स्थिति और आर्थिक जीवन पर गहरे और दीर्घकालिक असर डाले। बेटियों के जन्म को पौधारोपण से जोड़ने का यह प्रयोग समय के साथ एक *व्यापक ग्राम परिवर्तन आंदोलन* में बदल गया। इसने सामाजिक मानसिकता को बदला, पर्यावरणीय संसाधनों को पुनर्जीवित किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। सामूहिक श्रमदान, महिला भागीदारी और पंचायत की दूरदृष्टि ने मिलकर इसे एक ऐसा मॉडल बनाया, जहाँ लैंगिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ते हैं।

1. लैंगिक समानता

पिपलांत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने बेटियों के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहाँ बेटी का जन्म कई परिवारों में चिंता और उपेक्षा का कारण माना जाता था, वहीं अब वह पूरे गाँव का उत्सव बन गया है। पौधारोपण को बेटी जन्मोत्सव से जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि बेटी केवल परिवार की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की धरोहर बने। इस सांस्कृतिक परिवर्तन ने लैंगिक समानता की चेतना को गहरा किया और महिलाओं की पंचायत गतिविधियों तथा सामुदायिक निर्णय-प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाई।

2. पर्यावरणीय लाभ

पिपलांत्री ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण को अपने विकास मॉडल का केंद्र बनाया। अब तक तीन लाख से अधिक पौधे गाँव और उसके आसपास लगाए जा चुके हैं, जिसने हरित आच्छादन (green cover) को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। पहले जो गाँव सूखा-प्रवण और जल संकट से ग्रस्त था, वहीं अब तालाब, चेक डैम और बगीचों के कारण भूजल स्तर 800–900 फीट से सुधरकर 300–400 फीट तक पहुँच गया है। इसके साथ ही तापमान में औसतन 3–4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे जलवायु का संतुलन बेहतर हुआ है। इस प्रकार पर्यावरणीय दृष्टि से पिपलांत्री अब *पर्यावरण-संवेदनशील ग्राम विकास* का आदर्श उदाहरण बन चुका है।

3. आर्थिक परिवर्तन

पिपलांत्री की महिलाओं ने एलोवेरा और अन्य औषधीय पौधों की खेती को आजीविका का नया आधार बना लिया है। एलोवेरा से तैयार उत्पाद जैसे जेल, साबुन और औषधियाँ न केवल स्थानीय बाजार में बिकते हैं बल्कि स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के माध्यम से आसपास के कस्बों तक पहुँचते हैं। इससे महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके भीतर आत्मनिर्भरता का भाव गहराया है। वृक्षारोपण और जल-संरक्षण के कारण कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिससे गाँव की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई।

4. सामाजिक पूँजी

इस पहल का सबसे गहरा प्रभाव गाँव की सामाजिक पूँजी (*social capital*) पर पड़ा है। पौधों और बेटियों की देखभाल के लिए पूरे गाँव ने सामूहिक श्रमदान और साझा जिम्मेदारी का भाव अपनाया। इससे लोगों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास की भावना मजबूत हुई। अब पिपलांत्री केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक सामुदायिक परिवार की तरह कार्य करता है। यह सामाजिक एकजुटता ही है जिसने गाँव को मॉडल विलेज का दर्जा दिलाया और इसे भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

तालिका 17.1: पिपलांत्री पहल के प्रमुख परिणाम

क्षेत्र	परिणाम
वृक्षारोपण	3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए
जलस्तर	800–900 फीट से सुधरकर 300–400 फीट
तापमान	3–4°C की गिरावट
बेटियों की शिक्षा	सभी पंजीकृत बालिकाएँ विद्यालय में
महिला आय	एलोवेरा उत्पाद से 20–25% आय वृद्धि

स्रोत: क्षेत्र डेटा संग्रह से

मनरेगा डेटा (वित्तीय वर्ष 2023–24) और महिला भागीदारी: स्थिति और विश्लेषण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को भारत के ग्रामीण जीवन में “सामाजिक सुरक्षा की रीढ़” कहा जा सकता है। यह केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों को जीवन की कठिन परिस्थितियों में सहारा देने वाला कार्यक्रम है। वर्ष 2006 में लागू इस कानून का उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों को कम से कम सौ दिन का मजदूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित हो और इसके साथ ही गाँवों के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियाँ भी निर्मित हों। समय के साथ यह योजना केवल रोजगार गारंटी का साधन न रहकर महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता का एक प्रभावी माध्यम बन गई।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वित्तीय वर्ष 2023–24 में महिला श्रमिकों की भागीदारी अभूतपूर्व रही। इस वर्ष मनरेगा के तहत किए गए कार्य-दिवसों में महिलाओं का हिस्सा 58.8% से 59.25% तक पहुँच गया, जो पिछले एक दशक का सबसे ऊँचा स्तर था (द प्रिंट, 2024)। यदि पिछले पाँच वर्षों का रुझान देखें तो यह आँकड़ा लगातार बढ़ा है: 2019–20 में 54.7% से बढ़कर 2022–23 में

57.4% और अंततः 2023–24 में लगभग 59% तक पहुँच गया। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक नहीं है; यह इस बात का संकेत है कि ग्रामीण महिलाएँ अब योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और अपने परिवारों के आर्थिक जीवन में निर्णायक योगदान दे रही हैं।

राजस्थान के आँकड़े इस प्रवृत्ति को और भी रोचक बनाते हैं। यहाँ महिला भागीदारी का स्तर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक रहा है। 2018–19 से 2022–23 के बीच राजस्थान में महिलाओं की हिस्सेदारी 66% से 68% के बीच रही (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2023), इसका अर्थ है कि राजस्थान की महिलाएँ न केवल श्रमिक के रूप में बल्कि ग्राम पंचायतों की योजना और विकास प्रक्रिया में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

इसी पृष्ठभूमि में पिपलांत्री का उदाहरण विशेष महत्व रखता है। यह गाँव पहले खनन और जल संकट से जूझ रहा था, परंतु पंचायत और समुदाय की सामूहिक पहल ने इसे मॉडल गाँव बना दिया। यहाँ मनरेगा को केवल मजदूरी तक सीमित न रखकर वृक्षारोपण, तालाब निर्माण और चेक डैम जैसे कार्यों से जोड़ा गया। इन गतिविधियों ने गाँव को पर्यावरणीय सुरक्षा दी और साथ ही महिलाओं को बड़े पैमाने पर काम मिला। महिलाओं ने न केवल खेतों और बगीचों में श्रम किया बल्कि एलोवेरा और औषधीय पौधों की खेती में भी भागीदारी की। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन उत्पादों का विपणन हुआ, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई और वे परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्षम हुईं।

पिपलांत्री में मनरेगा की भूमिका इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इसने महिलाओं को केवल श्रमिक की भूमिका से आगे बढ़ाकर *सामाजिक परिवर्तन की नायिका* बनाया। उच्च महिला भागीदारी ने ग्राम पंचायत की जवाबदेही और पारदर्शिता को भी मजबूत किया। जब महिलाएँ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और रख-रखाव में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो योजनाओं का असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। मनरेगा ने पिपलांत्री जैसी पंचायतों में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सक्रिय बनाने का काम किया है। इस कार्यक्रम के भीतर उच्च महिला भागीदारी ने न केवल आय और रोजगार का विस्तार किया, बल्कि आत्मसम्मान और सामुदायिक चेतना को भी बढ़ाया। पिपलांत्री यह दिखाता है कि जब पंचायत केवल नीति लागू करने वाली संस्था न रहकर समुदाय की आकांक्षाओं को केंद्र में रखे, तब विकास “अनुभव से नीति और संवाद से परिवर्तन” की वास्तविक यात्रा बन जाता है।

अलग-अलग स्रोत अनुसार, पिपलांत्री में अब तक 3 लाख से अधिक वृक्ष लगाए जा चुके हैं; जलस्तर में 800–900 फीट की रिकवरी हुई, तापमान में 3–4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है; पर्यावरण में विविधता और हरियाली लौट आई है। साथ ही, एलोवेरा को बचाने और उसका बिक्री प्रारूप अपनाने से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका का अवसर मिला। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी।

सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) के संदर्भ में पिपलांत्री

पिपलांत्री का अनुभव यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायतें यदि चाहें तो सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को केवल एक अंतरराष्ट्रीय एजेंडा भर न मानकर, उन्हें स्थानीय संदर्भों में मूर्त रूप दे सकती हैं। इस छोटे-से गाँव ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा और पंचायत आधारित नेतृत्व के माध्यम से कई लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस योगदान दिया है।

सबसे पहले, गरीबी उन्मूलन (SDG 1) के संदर्भ में देखें तो एलोवेरा और अन्य औषधीय पौधों की खेती ने महिलाओं और किसानों को नई आजीविका दी। इससे न केवल परिवारों की आय बढ़ी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी आई। लैंगिक समानता (SDG 5) के क्षेत्र में पिपलांत्री की पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बेटी का जन्म अब बोझ नहीं बल्कि पूरे गाँव का उत्सव है। शिक्षा की गारंटी और समय से पूर्व विवाह न करने की शर्तों ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया और लैंगिक न्याय की दिशा में नई दृष्टि दी। स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG 6) की दिशा में भी गाँव ने उल्लेखनीय प्रगति की। वृक्षारोपण, तालाब निर्माण और चेक डैम जैसी गतिविधियों ने जलस्तर को पुनर्जीवित किया। पहले जहाँ पानी 800–900 फीट नीचे था, वहीं अब यह 300–400 फीट की गहराई पर उपलब्ध है। इसने गाँव को सूखा-प्रवण स्वरूप से बाहर निकालने में मदद की।

जलवायु कार्रवाई (SDG 13) के संदर्भ में पिपलांत्री का मॉडल यह दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर भी जलवायु संकट का समाधान संभव है। लाखों पौधों ने न केवल तापमान में औसतन 3–4 डिग्री की गिरावट लाई, बल्कि वातावरण को अधिक संतुलित और स्वास्थ्यप्रद भी बनाया। स्थलीय पारिस्थितिकी (SDG 15) के क्षेत्र में यह पहल और भी प्रासंगिक है। गाँव में हरित आच्छादन व्यापक रूप से बढ़ा, जैव विविधता लौट आई और खेती के लिए नई संभावनाएँ बनीं। इससे ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक संसाधन दोनों को स्थायित्व मिला।

इस प्रकार पिपलांत्री यह प्रमाणित करता है कि सतत् विकास लक्ष्य केवल कागजी संकल्प नहीं हैं। यदि पंचायतें सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय नवाचार को प्राथमिकता दें तो ये लक्ष्य गाँवों की ज़मीन पर भी उतने ही जीवंत हो सकते हैं।

नीति-सुझाव और अनुकरणीय पहल

पिपलांत्री मॉडल यह स्पष्ट करता है कि जब स्थानीय संस्कृति, पंचायत नेतृत्व, पर्यावरणीय संरक्षण और लैंगिक न्याय एक साथ काम करते हैं तो सतत् विकास की दिशा केवल आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से संभव हो जाती है। इस पहल ने यह साबित किया कि कोई भी सामाजिक परंपरा यदि ग्राम पंचायत के संस्थागत ढाँचे और योजनाओं से जुड़ जाए तो वह दीर्घकालिक परिवर्तन का आधार बन सकती है। इसलिए अन्य पंचायतों के लिए पिपलांत्री से कई महत्वपूर्ण सीखें निकलती हैं।

सबसे पहले, बेटी जन्मोत्सव को सामुदायिक उत्सव बनाना इस मॉडल का मूल है। यह केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो पूरे समुदाय को एक साझा उद्देश्य से जोड़ता है। इसके साथ-साथ पौधारोपण और पर्यावरणीय गतिविधियों को ग्राम पंचायत की विकास योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि गाँव का प्राकृतिक संतुलन कायम रहे और जलवायु संकट से निपटने की क्षमता बढ़े। इसी तरह, बेटियों की शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है, ताकि यह पहल केवल प्रतीकात्मक न रहे बल्कि महिलाओं और बेटियों के जीवन में ठोस बदलाव ला सके।

नीतिगत स्तर पर यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में लैंगिक और पर्यावरणीय संकेतकों को समाविष्ट किया जाए। यदि योजना निर्माण में इन बिंदुओं को अनिवार्य कर दिया जाए तो पिपलांत्री जैसे प्रयोग पूरे देश में फैल सकते हैं। साथ ही, वृक्षारोपण और बागवानी जैसी गतिविधियों को महिला स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ना चाहिए, ताकि आजीविका और पर्यावरणीय संरक्षण एक साथ आगे बढ़ें। ग्राम सभा की नियमित समीक्षा इस पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाती है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि पौधों की देखभाल और बेटियों की शिक्षा पर परिवार और समुदाय लगातार ध्यान देते रहें।

हालाँकि, इस मॉडल को बड़े स्तर पर लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है निरंतर सामुदायिक भागीदारी को बनाए रखना, क्योंकि समय के साथ सामाजिक ऊर्जा कम हो सकती है। इसके अलावा, संसाधनों की उपलब्धता और संस्थागत सहयोग भी बेहद आवश्यक है। नीति स्तर पर ऐसी पहलों को बढ़ावा देना और पंचायतों को आवश्यक वित्तीय व प्रशासनिक सहायता प्रदान करना इस दिशा में मददगार होगा। इस प्रकार पिपलांत्री यह दिखाता है कि यदि स्थानीय परंपरा और आधुनिक पंचायत शासन का संयोजन हो, तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति केवल अंतरराष्ट्रीय संकल्प तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गाँवों की ज़मीन पर भी साकार हो सकती है।

निष्कर्ष

पिपलांत्री बताता है कि विकास योजनाएँ तभी सफल होती हैं जब वे समुदाय की संस्कृति और संवेदना से जुड़ती हैं। यहाँ बेटी सम्मान है, बगिया भविष्य है और पंचायत उसका सूत्रधार है। पिपलांत्री एक गाँव नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है जहाँ बेटी की अपेक्षा और उपेक्षा के बीच, हर बेटी को गहराई से सम्मान मिला। पिपलांत्री केवल एक गाँव नहीं, बल्कि *आशा और नवाचार का प्रतीक* है। पिपलांत्री गाँव यह बताता है कि विकास केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि संस्कृति और सामूहिक चेतना का परिणाम है। यह सिखाता है कि जब स्थानीय नेतृत्व, पंचायत की संस्थागत ताकत और समुदाय की सामूहिक चेतना एक साथ आती हैं, तो संसाधनों की

कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह भी विकास की बाधा नहीं बन पाते। यह गाँव इस बात का प्रमाण है कि “गाँव केवल योजनाओं का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार और नीतिगत प्रयोग का सक्रिय केंद्र भी हो सकता है।” पिपलांत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे दो ऐसे विषयों को जो अक्सर अलग-अलग नीति क्षेत्रों में देखे जाते हैं, एक ही सामाजिक परंपरा के जरिये जोड़ दिया।

इस पहल ने साबित किया कि ग्राम पंचायतें यदि चाहें तो सतत विकास लक्ष्यों को केवल “अंतरराष्ट्रीय एजेंडा” न मानकर स्थानीय वास्तविकताओं से जोड़ सकती हैं। शोध और अकादमिक दृष्टि से पिपलांत्री का अनुभव यह दिखाता है कि “अनुभव से नीति” कोई नारा नहीं बल्कि व्यावहारिक हकीकत है। यहाँ के अनुभव नीतियों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास केवल आर्थिक सूचकांकों से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन, संबंधों और संस्कृति से परिभाषित होता है। भविष्य की दिशा में यह जरूरी है कि ऐसे मॉडल गाँवों की कहानियाँ केवल मीडिया की सुर्खियों में न रह जाएँ, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, नीति निर्माण और अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाए। यदि पिपलांत्री जैसे प्रयोगों को अन्य पंचायतें सीखकर अपनाएँ, तो भारत में ग्राम विकास का चेहरा और अधिक आत्मनिर्भर, समावेशी और पर्यावरण-संवेदनशील हो सकता है। इस प्रकार, पिपलांत्री न केवल राजस्थान का, बल्कि पूरे भारत का एक “आशा का गाँव” है जहाँ बेटी सम्मान है, बगिया भविष्य है और पंचायत उसका सूत्रधार है।

संदर्भ

- आइडियाज़ फ़ॉर इंडिया. (2025). *मनरेगा का संक्षिप्त इतिहास: 20 साल, 10 चार्ट्स में* आइडियाज़ फ़ॉर इंडिया. <https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/a-short-history-of-mnrega-20-years-in-10-charts.html>
- आईजेएसआरएसटी (IJSRST). (2017). *इको-फेमिनिज्म और सतत ग्रामीण विकास: पिपलांत्री का अध्ययन*। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ साइंटिफ़िक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3(5), 52–59. <https://ijsrst.com/paper/10167.pdf>
- इंडियन एक्सप्रेस. (2023). *मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है*। इंडियन एक्सप्रेस. <https://indianexpress.com/article/india/women-participation-in-nregs-continues-to-rise>
- ग्लोबल बिज़नेस सर्विफ़िकेशन इंक. (GBCI). (2019). *इट टेक्स अ विलेज टू सेव द प्लानेट: पिपलांत्री, राजस्थान*. <https://www.gbci.org/it-takes-village-save-planet-piplantri-rajasthan>

- द ट्रिब्यून इंडिया. (2024). *हर बेटी के लिए 111 पेड़: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गाँव की सराहना की* द ट्रिब्यून. <https://www.tribuneindia.com/news/india/111-trees-for-every-girl-child-sc-lauds-rajasthan-villages-intlative>
- द प्रिंट. (2024). *मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँची*, द प्रिंट. <https://theprint.in/india/womens-participation-in-mnregas-hits-10-yr-high-at-58-8>
- भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय. (2011). *भारत की जनगणना 2011: अस्थायी जनसंख्या आँकड़े*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार। <https://censusindia.gov.in>
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB). (2023, 12 जुलाई). *मनरेगा में महिला भागीदारी पर प्रेस नोट [प्रेस विज्ञप्ति]*. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942377>
- मिशन सस्टेनेबिलिटी. (2024). *द पिपलांत्री मॉडल: इकोलॉजी और कम्युनिटी का संगम*. <https://mssionsustainability.org/blog/the-piplantri-model>
- येल रिव्यू ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़. (2016). *राजस्थान में हरियाली और नारीवाद: पिपलांत्री गाँव में जमीनी मरुस्थलीकरण से संघर्ष*. येल रिव्यू ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़. <https://yrls.ylra.org/essays/growing-up-green-in-rajasthan>
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2021). *भारत में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण: ग्राम पंचायतों की भूमिका*. यूएनडीपी इंडिया. <https://www.undp.org/India/publications>